जनसत्ता

घिरता पाकिस्तान

पाकिस्तान में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को नष्ट करने की भारत की कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोरदार समर्थन मिल रहा है। कई देशों ने इस कार्रवाई को जायज बताते हुए पाकिस्तान को चेताया है कि वह अब आतंकवाद फैलाना बंद कर दे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक बड़ी कामयाबी यह है कि फ्रांस भी इस अभियान में भारत के साथ आ गया है। उसने कहा है कि वह जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में काम कर रहा है। दरअसल, फ्रांस को अगले महीने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का अवसर मिलेगा और उसका कहना है कि वह मसूद अजहर पर पाबंदी से संबंधित प्रस्ताव को प्रतिबंध समिति के समक्ष रखेगा। वह जिस तेजी से इस प्रस्ताव को तैयार करने में जुटा है उससे उम्मीद है कि इस बार सुरक्षा परिषद में यह दांव खाली नहीं जाएगा और मसूद अजहर पर पाबंदी लगवाने के भारत के प्रयासों को सफलता मिलेगी। अगर यह प्रस्ताव पेश हो जाता है तो संयुक्त राष्ट्र में पिछले दस साल में यह चौथा मौका होगा जब अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की मांग की जाएगी।

लेकिन इस बार भी देखने की बात यह है कि मसूद अजहर पर पाबंदी को लेकर चीन का रुख क्या रहता है। सुरक्षा परिषद में जब-जब यह मामला गया है, चीन ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया और मसूद अजहर को आतंकवादी मानने से इनकार कर दिया। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि भारत की संसद पर हमला, मुंबई हमला, उड़ी, पठानकोट और नगरोटा जैसे हमलों को जैश ने ही अंजाम दिया था। भारत सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों से इस बात को उठा चुका है और सबूत तक पेश किए हैं। लेकिन यह हैरानी की बात है कि पर्याप्त सबूत होने के बावजूद चीन मसूद अजहर को आतंकी नहीं मानता। अगर चीन ने इस मसले पर भारत का साथ दिया होता तो मसूद सहित पाकिस्तान पर कब का शिकंजा कस गया होता। लेकिन अब फ्रांस और अन्य देश आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरह भारत के साथ खड़े हुए हैं, वह चीन जैसे देशों के लिए बड़ा संदेश है। चीन की यात्रा पर गईं भारत की विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में चीन को बता दिया है कि पाकिस्तान अब तक जिस तरह जैश-ए-मोहम्मद और उसके आका मसूद अजहर को समर्थन देता आया है, भारत की कार्रवाई उसी का जवाब है।

भारत ने पाकिस्तान में चल रहे जैश के ठिकानों को तो नष्ट किया ही है, साथ ही दुनियाभर में उसके खिलाफ जो कूटनीतिक अभियान शुरू किया है, उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। चौवालीस देशों में तैनात भारत के रक्षा राजनयिकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे पाकिस्तान को बेनकाब करें। आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी मौजूदा घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की है और भारत के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। आस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि वह अपने यहां चल रहे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे। अमेरिका भी कई बार पाकिस्तान को चेता चुका है कि वह अपने यहां मौजूद आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे। अमेरिका ने तो पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद बंद करने जैसे कदम भी उठाए हैं। यूरोपीय संघ के कई देश पहले ही आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये देश भी पाकिस्तान के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होते देखना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के सामने एकमात्र यही रास्ता है कि वह भारत के बजाय मसूद अजहर जैसे आतंकियों और जैश, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ युद्ध-अभियान छेड़े और इनका खात्मा करे।

जवाबदेही की खबर

खबरें अगर सच या तथ्य की कसौटी पर खरी नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि वे भ्रामक प्रचार या किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। जाहिर है, ऐसी खबर अपने असर में आमतौर पर नुकसान ही पहुंचाती है। लेकिन अगर किन्हीं वजहों से माहौल संवेदनशील हो तो ऐसे में अनजाने में भी कोई तथ्यहीन खबर बड़े विनाश की वजह बन सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर फिलहाल जिस तरह के तनाव पैदा हो गए हैं, उसमें खबरों की दुनिया से जुड़े लोगों की जवाबदेही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के मीडिया में भारतीय विमानों को मार गिराने और घायल पायलट से संबंधित जैसी भ्रामक खबरें और फर्जी तस्वीरें न केवल सोशल मीडिया पर फैल गईं, बल्कि टीवी चैनलों पर भी उनके प्रसारण के लिए जिस तरह गैरजरूरी बेलगाम आक्रामक तेवर का सहारा लिया गया, उसका मकसद लोगों की भावनाएं भड़काने के सिवा और क्या हो सकता है! विमान मार गिराने के दावे के साथ कई साल पुराने किसी अन्य जगह हुए विमान हादसे और घायल पायलट की तस्वीर को प्रसारित कर दिया गया।

हालांकि आज ऐसी तकनीकें मौजूद हैं, जिनके जरिए खबरों, फोटो या वीडियो के असली या फर्जी होने के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की ओर से जारी फर्जी वीडियो तुरंत पकड़ में आ गए। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान के ठिकाने से अपनी आतंकी गतिविधियों को संचालित करने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय पाकिस्तान को झूठ फैलाने के अभियान का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है! ऐसा भारत में मौजूद टीवी चैनलों में भी हो रहा हो सकता है। आज हालत यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं और दूसरी ओर सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक पर ऐसी खबरें भी परोसी जा रही हैं जिनका सच से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वे आम जनता के बीच भ्रम और गैरजरूरी उत्तेजना पैदा करने की वजह बन रही हैं। साधारण लोग वीडियो जैसे समाचार के स्रोत पर ज्यादा आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इसी का फायदा उठाने के क्रम में कुछ टीवी चैनल हड़बड़ी में बिना पुष्टि किए फर्जी वीडियो भी प्रसारित कर देते हैं, जो लोगों की भावनाएं भड़काने के काम आते हैं।

यह किसी से छिपा नहीं है कि अगर जनता के व्यापक हिस्से में उन्माद जैसी प्रतिक्रिया सामने आती है तो कई बार सरकारों को उसे संभालने या उससे प्रभावित होकर फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इस बात की संवेदनशीलता को समझे बगैर कई टीवी चैनलों के बीच एक तरह से होड़ मच गई है कि वे मुनाफे के मकसद से युद्ध से जुड़ी भावनाओं के कारोबार के लिए खबरों को कितने आक्रामक तरीके से परोस सकते हैं। दुनिया भर में युद्ध अपने आप में सबसे संवेदनशील स्थिति है। यह जगजाहिर तथ्य है कि युद्ध के बाद उससे हुए नुकसानों की भरपाई करना बेहद मुश्किल होता है और उसमें लंबा वक्त लग जाता है। कई बार सामान्य तनाव के हालात को युद्ध तक पहुंचाने में कुछ अफवाहों या झूठी खबरों का बड़ा हाथ होता है। आज आधुनिक तकनीकी से लैस मीडिया के अलग-अलग रूपों का प्रसार जिस स्तर पर पहुंच गया है, उसमें वह किसी खबर के तेजी से साधारण लोगों तक पहुंच का एक जरिया बन गया है। ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह बिना पुष्टि के ऐसी खबरें प्रसारित न करे जो लोगों तक गलत जानकारी पहुंचाएं और उनकी भावनाएं भड़काएं।

कल्पमेधा

मूर्ख घर में पूजा जाता है, मुखिया गांव में पूजा जाता है। राजा की पूजा राज्य में होती है परंतु विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है।

-चाणक्य

तनावों में उलझती दुनिया

भारत डोगरा

विश्व पर आधिपत्य को लेकर मानव इतिहास में बहुत विनाशकारी युद्ध हुए हैं। बीसवीं शताब्दी में दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। तब से अब तक विनाशकारी हथियारों की मारक क्षमता हजारों गुना बढ़ चुकी है और इतने परमाणु हथियार भंडारण में हैं कि विश्व के अधिकांश जीवन को कई बार समाप्त कर सकते हैं।

हाल में ऐसे संकेत मिले हैं कि विश्व नए और बड़े तनावों में उलझता जा रहा है। जबकि कुछ बड़े तनाव जो बहुत समय से सुलझाए नहीं गए हैं, वे बने हुए हैं। अनेक राजनीतिक विश्लेषकों ने कुछ समय पहले कहना शुरू किया कि विश्व में नए शीत युद्ध के समीकरण तैयार हो रहे हैं। पिछले शीत युद्ध में एक ओर अमेरिका के नेतृत्व में मुख्य पूंजीवादी देश थे और दूसरी ओर सोवियत संघ व उससे जुड़े अनेक साम्यवादी देश थे। परमाणु हथियारों से लैस ये दोनों गुट अनेक दशकों तक परस्पर संदेह, प्रतिस्पर्धा और तनावों के दौर में रहे। कभी-कभी वास्तविक युद्ध के नजदीक आए पर उनकी और दुनिया की खुशकिस्मती रही कि उनमें परमाणु हथियारों के उपयोग वाला कोई खुला युद्ध नहीं हुआ। अलबत्ता पूरी तैयारी की स्थिति में परमाणु हथियारों को तैयार जरूर रखा गया। इन दो गुटों में प्रत्यक्ष खुला युद्ध न होने पर भी अनेक क्षेत्रों में इन गुटों के बीच छाया युद्ध होते रहे, यानी दोनों गुटों का शक्ति परीक्षण अन्य देशों की धरती पर होता रहा। इन छाया युद्धों में भी लाखों लोग मारे गए और भयंकर तबाही हुई।

सोवियत संघ व उसके नजदीकी प्रभाव क्षेत्र के विघटन के बाद प्रायः माना गया कि अब शीत युद्ध का अंत हो गया है। पर कुछ समय बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच फिर से तनाव बढ़ने लगा। इतना ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच भी व्यापारिक व सामरिक दोनों स्तरों पर तनाव तेजी से बढ़ रहा है। महाविनाशक हथियारों के वास्तविक उपयोग के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस में जो समझौते पहले हो चुके थे, उनका नवीनीकरण समय पर नहीं हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 20 दिसंबर 2018 को कहा कि इस कारण इतनी बड़ी तबाही का संकट उत्पन्न हो सकता है जिससे पूरी धरती ही तबाह हो जाएगी। इसके पहले अमेरिका ने रूस पर महाविनाशक हथियारों का उपयोग रोकने वाली संधियों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। चीन भी सबसे विध्वंसक हथियारों में व विशेषकर नए रोबोट हथियारों में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है।

ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि निकट भविष्य में विश्व में किस महाशक्ति का दबदबा अधिक तेजी से बढ़ेगा? यह सवाल राजनीतिक, सामरिक व आर्थिक सभी संदर्भों में पूछा जा रहा है। पर इससे बड़ी बुनियादी बात यह है कि जब तक विश्व में आधिपत्य की होड़ जारी रहेगी तब तक विश्व के तनाव दूर नहीं होंगे। विश्व पर आधिपत्य को लेकर मानव इतिहास में बहुत विनाशकारी युद्ध हुए हैं। बीसवीं शताब्दी में दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। तब से अब तक विनाशकारी हथियारों की मारक क्षमता हजारों गुना बढ़ चुकी है और इतने परमाणु हथियार भंडारण में हैं कि विश्व के अधिकांश जीवन को कई बार समाप्त कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने यह है कि आधिपत्य की इस दौड़ को बिना किसी बड़ी हिंसा के समाप्त कर दिया जाए। एक ओर इतने विध्वंसक हथियारों का भंडार हो और दूसरी ओर इनसे संपन्न महाशक्तियां निरंतर संदेह, तनाव और दुश्मनी के भाव से रहें तो किसी भी समय अनहोनी घट सकती है। इसलिए समय रहते इन तनावों और दुश्मनी और आधिपत्य की होड़ का शांतिजनक समाधान निकालना जरूरी है।

व्यापार के नियम ऐसे होने चाहिए जो किसी के आधिपत्य को न बढ़ाएं, अपितु न्यायसंगत हों, सभी देशों की जनता के हित में हों। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का सवाल और भी महत्त्वपूर्ण है। इस समय एक कृत्रिम स्थिति यह है कि अमेरिका की मुद्रा डॉलर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की मान्यता प्राप्त है। यह फैसला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विशेष स्थितियों में लिया गया था। उस समय भी यह विवादास्पद था, पर बाद में रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रपति काल में जब अमेरिका ने एकतरफा 'गोल्ड स्टैंडर्ड' से हटने का निर्णय लिया तो इस पर और भी सवालिया निशान लग गए। पहले अमेरिका की ओर से औपचारिक गारंटी थी कि अमेरिकी डॉलर के बदले में सोना उपलब्ध है। पर इस गारंटी को एकतरफा निर्णय से हटा लिया गया। अमेरिका के कर्ज बढ़ने से भी अमेरिकी डॉलर की सर्वमान्यता पर सवाल उठने लगे। केवल अमेरिका की सैन्य शक्ति के बल पर

डॉलर कब तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में बना रहेगा, इसके बारे में आज भी सवाल कायम हैं।

सोवियत संघ का विघटन एक दिन होना ही था। अच्छा हुआ कि वह बिना किसी बड़े युद्ध के हो गया। पर उसके बाद शीत युद्ध समाप्त कर अमन-शांति का नया दौर आरंभ करने का जो बड़ा अवसर विश्व को मिला था, वह उसने खो दिया। इसकी वजह मूल प्रवृत्ति आधिपत्य की थी। बड़े पूंजीवादी देशों ने सोचा कि यह समय रूस को दबाने का है। पर रूस ने अपनी सामरिक शक्ति की एक सीमा तक रक्षा की और फिर नए शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। अब तो बस यही उम्मीद है कि निकट भविष्य में तेजी से बढ़ते तनावों का संतोषजनक समाधान अमन-शांति के माहौल में प्राप्त कर लिया जाए। इसके लिए विश्व स्तर पर अमन-शांति के जनांदोलन को मजबूत करना होगा।

जलवायु बदलाव जैसी विभिन्न गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं हों या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा व व्यापार की समस्याएं हों, उनके समाधान के लिए ऐसा माहौल चाहिए जिसमें बड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते हो सकें। समस्या यह है कि विश्व के अधिकांश देश या तो अभी तक आधिपत्य आधारित सोच से ग्रस्त हैं, या अपने देश में चुनावी लाभ के लिए वे संकीर्ण सोच को भड़काना चाहते हैं। ऐसे में विश्व को स्थायी अमन-शांति की ओर ले जा पाने के प्रयास विफल हो रहे हैं। सीरिया व यमन जैसे कुछ देशों में इस समय हिंसा से बहुत तबाही हो रही है और इसे तत्काल कम करने की संभावनाएं मौजूद हैं। जबकि दूसरी ओर अफगानिस्तान जैसे कुछ अन्य देशों की स्थिति और जटिल है। यूक्रेन और ईरान ऐसे देश हैं जहां तनावों को युद्ध की ओर बढ़ने से समय रहते रोका जा सकता है।

जिस तरह की गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं वैश्विक स्तर पर मौजूद हैं, वे जीवन के अस्तित्व मात्र को खतरे में डाल सकती हैं। जलवायु संकट ऐसी एक समस्या है, पर ऐसी ही गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं और भी हैं। दूसरे शब्दों में, एक हद तक बढ़ने के बाद ये समस्याएं मनुष्य के नियंत्रण के बाहर हो सकती हैं और धरती की जीवनदायिनी क्षमता ही खतरे में पड़ सकती है। इस स्थिति में यह बहुत जरूरी है कि इसे एक मूल प्राथमिकता बना कर विभिन्न देश इन पर्यावरणीय समस्याओं के समय पर समाधान के लिए निरंतरता से सहयोग करें।

पर क्या यह सहयोग ऐसी स्थिति में हो सकता है जब युद्ध हो रहे हों या युद्ध का खतरा मंडरा रहा हो या इससे जुड़े तनाव एक-एक कर घेर रहे हों? ऐसी स्थितियों में सबसे महत्त्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए निरंतरता से, आपसी विश्वास पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सहयोग नहीं बन सकता। अतः इन गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान हो या महाविनाशक हथियारों से उत्पन्न संकट का समाधान हो, निरंतरता से अमन-शांति का विश्व स्तर पर माहौल बनाना आज बहुत जरूरी है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर शांति के ऐसे अभियान निरंतरता से चलने चाहिए जो सभी तरह की संकीर्णताओं से मुक्त हों और विश्व के सभी लोगों की भलाई के लिए बिना किसी भेदभाव के समर्पित हों।

एक सभ्य समाज में

पारुल जैन

दुनिया मेरे आगे

प्रकृति ने स्त्री और पुरुष के बीच लैंगिक आधार पर काम तय नहीं किए हैं। वह तो हमारे समाज की देन है। स्त्रियों को लेकर समाज अक्सर पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होता है। मसलन, वे नाजुक होती हैं, मेहनत के काम करने में थोड़ा पीछे रहती हैं, अकेली कहीं आना-जाना नहीं कर सकतीं। न ही अकेले घूम-फिर सकती हैं। प्लेटो, अरस्तू और रूसो जैसे दार्शनिकों ने कोमलता और भावुकता जैसे गुण स्त्री के लिए और वीरता और बल जैसे गुण पुरुषों के बताए हैं। स्त्री को शुरू से ही बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ नहीं समझा गया। कई पुरुष उन्हें कमतर समझते हैं। उन्हें लगता है कि स्त्रियां बुद्धि और बल दोनों में ही उनसे कमतर हैं और इसी आधार पर स्त्रियों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। शहरों में तो फिर भी हालात एक हद तक सही, ठीक हैं। लेकिन अगर ग्रामीण और सुदूर इलाकों की बात करें तो स्थिति सही नहीं लगती, लेकिन पिछले दिनों एक सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल होने के मकसद से जब मणिपुर जाना हुआ तो समाज में मौजूद कई धारणाओं के उलट बातें देखने को मिलीं। हालांकि देश के दूसरे हिस्सों और खास तौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों में तमाम महिलाओं ने अपनी मेहनत और ज्ञान से साबित किया है कि उनके बारे में पूर्वधारणाएं गलत हैं। लेकिन मणिपुर में मेहनतकश और समझदार स्त्रियां आम हैं। इसकी वजह यह होगी कि वहां सार्वजनिक गतिविधियों में महिलाओं के लिए ज्यादा और बेहतर मौके हैं। और मेरा मानना है कि जहां मौका मिलता है, वहां एक वंचित व्यक्ति अपनी क्षमता साबित कर ही देता है।

तो मणिपुर के सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की भूमिका और भागीदारी किसी जड़ व्यक्ति को विस्मित कर सकती है। उन व्यवसायों में भी उनकी मौजूदगी आम दिखी, जिन पर उत्तर भारत में पुरुषों का वर्चस्व माना जाता है। ज्यादातर दुकानों की मालकिन महिलाएं थीं। बल्कि वहां का इमा बाजार इसी बात के लिए मशहूर है। यह इंफल का सबसे बड़ा बाजार है, जहां सब्जी और फल से लेकर कपड़े और जूते तक सब कुछ मिलता है। करीब चार हजार दुकानों से सजे इस बाजार में सभी दुकानदार महिलाएं थीं, जिनकी उम्र अठारह साल से लेकर अस्सी साल तक थी। कई बुजुर्ग महिलाओं ने अपने साथ रेडियो रखा हुआ था और फिल्मों के गीत सुनते हुए मस्ती में सामान बेच रही थीं।

'इमा' शब्द मतलब है मां। इस बाजार में आकर ऐसा लगता है कि जैसे मां अपने बच्चों के लिए रोटी बनाने के साथ साथ सम्मान के साथ रोटी कमाती है। वहां लगभग पचपन साल की मूर्ति जी से मुलाकात हुई। यों वे राजस्थान के कोटपुतली की हैं पर इंफल में उनकी दुकान है, जहां वे कंबल बेचती हैं। जहां दिल्ली में सड़कों पर नजर पर जोर डालने के बाद कहीं कोई लड़की या महिला मोटरसाइकिल चलाती दिखती है, वहां मुझे लड़कियां धड़ल्ले से स्कूटी और कार चलाती दिखीं। इसके अलावा, मेरी मुलाकात एक के बाद एक कई स्वावलंबी महिलाओं से हुई, चाहे वे पर्यटकों को अपनी बैटरी कार में कंगला फोर्ट घुमाती पच्चीस वर्षीय मलेयम हो या बीस वर्षीय फीफी हो जो पढ़ने के साथ-साथ उत्सवों के मौके पर केले और आलूबुखारे से पेय बना कर बेचती हैं। कई जगह स्त्रियां अपने छोटे बच्चों को पीठ पर बिठा कर कपड़े से बांध कर अपने रोजमर्रा के काम निपटाती नजर आईं। उत्तर भारत के लिए ये बातें खास होंगी, लेकिन वहां के लिए आम थीं।

मैं जिन विमानों से दिल्ली से मणिपुर गई और आई, उनकी पायलट महिला ही थीं। वहां से दिल्ली लौटते समय जब विमान में महिला पायलट के नाम की उद्घोषणा हुई तो मणिपुर से इतने सारे अनुभव लिए मैं मैरी कॉम, दीपा कर्मकार, कल्पना चावला, अरुणिमा सिन्हा या अवनि चतुर्वेदी के बारे में सोच रही थी। ये उन बहुत से नामों में से कुछ हैं जिनकी कामयाबी के बारे में हम सब जानते हैं। इनके अलावा भी ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं, जिनकी कामयाबियों और कारनामों को शायद हम कभी न जान पाएं, मगर वे सब अपने क्षेत्र में अव्वल हैं और खामोशी से अपना काम करते हुए स्त्रियों की दुनिया और अपने देश के उत्थान में अपनी भूमिका निभा रही हैं। हां, यह सच है कि देश भर में पत्रकार, लेखक, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, क्लर्क या फिर किसी व्यवसाय में लगी तमाम महिलाएं भी इसी मुहिम का हिस्सा हैं, जो चुपचाप घर और बाहर, दोनों ही मोर्चों पर अपना काम कर रही हैं। स्त्रियों को अगर अधिकार के रूप में थोड़ा सम्मान और समाज का साथ मिल जाए तो ये क्या नहीं कर सकतीं! यह अलग बात है कि हमारे देश और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में आज भी आगे बढ़ती और कामयाबी के परचम लहराती महिलाएं खास लगती हैं। जबकि हर स्तर पर महिलाओं को बराबरी का हक किसी भी सभ्य समाज में आम होना चाहिए।

दोहरा मोर्चा

पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस कर जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस साहसिक और असरदार कार्रवाई में भारतीय वायुसेना के बारह मिराज-2000 विमानों ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट और मुजफ्फराबाद, चकोटी इलाके में जैश के ठिकानों पर बमबारी कर आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों, प्रशिक्षण शिविरों और उनमें प्रशिक्षण ले रहे करीब 300 फिदायीन हमलावरों व प्रशिक्षकों को धराशायी कर दिया। इस आपरेशन की सबसे खास बात यह रही कि सभी लड़ाकू विमान आपरेशन को अंजाम देकर पूरी तरह सुरक्षित लौट आए। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान हाई अलर्ट पर था लेकिन भारतीय वायुसेना के इस अदम्य साहस के आगे पाकिस्तान के सारे सुरक्षा तंत्र पस्त हो गए।

भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान सकते में है और इमरान सरकार को सीनेट के अंदर भी शर्मसार होना पड़ा है। दरअसल, इस कार्रवाई के पीछे तीन कारक हैं जो भारत की वैश्विक स्तर पर नापाक हरकतों का जवाब देने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। पहला, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व रीढ़ के समान होता है। पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का कद काफी बढ़ा है और सभी देशों में भारत के प्रति भरोसा उत्पन्न हुआ है जो अहम कूटनीतिक सफलता है। यही कारण है कि इस कार्रवाई के बाद सारे देश पाकिस्तान को नसीहत दे रहे हैं। दूसरा कारक है 'सैन्य शक्ति'। यह निर्विवाद तथ्य है कि भारतीय सेना को जब-जब देश की हिफाजत करने के लिए कोई सैन्य आपरेशन करने की जिम्मेदारी मिली है, उसने अपने पराक्रम, साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। यही कारण है कि मौजूदा कार्रवाई में पाकिस्तान का कोई भी आम नागरिक हताहत नहीं हुआ क्योंकि हमारी सेना का संकल्प आतंकियों के खात्मे का था। इस बात को भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी साफ कर दिया गया। तीसरा महत्त्वपूर्ण कारक है 'जन समर्थन और देशभक्ति'। भारत के जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश का लहर दौड़ गई थी। लोगों के भीतर जिस प्रकार आतंकियों और उनकी पनाहगाह पाकिस्तान के प्रति गुस्सा था, उसने देशभक्ति का संचार किया और हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया।

भारत की जवाबी कार्रवाई से जैश के संगठन को जरूर करारी चोट पहुंची है पर हमें यह ध्यान देना है कि कश्मीर की समस्या अभी हल नहीं हुई है और न ही पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन अभी खत्म हुए हैं। लिहाजा, बौखलाहट में वह जरूर कोई नापाक हरकत कर सकता है। यह भी हैरानी की कोई बात नहीं होगी कि पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ आतंकी संगठनों को भारत में हमले के लिए भेजे। ऐसे में हमें आतंकियों और पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए दोहरे मोर्चे पर तैयार रहना है।

● *शिवांशु राय, नई दिल्ली*

सतर्कता जरूरी

आज कश्मीर घाटी अशांति के दौर से गुजर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक पर्यटक स्थल आतंकी स्थल में तब्दील हो जाएगा। वर्षों से कश्मीर फिल्म निर्माताओं और सिने सितारों की पहली पसंद रहा है पर आज वहां कोई नहीं जाना चाहता। भारत के लिए आतंकवाद कैंसर जैसा हो गया है। देश आतंकवाद से दोहरी लड़ाई भी लड़ रहा है। एक जंग अपने ही देश में बैठे गद्दारों से है और दूसरी पाक में बैठे आतंकियों से है। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर कदम उठाए हैं लेकिन सभी देशवासियों को भी सतर्क रह कर आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त करना होगा।

● *आशीष, राम लाल आनंद कॉलेज, दिल्ली*

गिरता स्तर

भारत में पिछले कुछ समय से तमाम खबरिया टीवी चैनलों का स्तर गिरता जा रहा है। पहले बात 'डिबेट' के नाम पर चिल्लाने तक सीमित थी, लेकिन अब गलत जानकारी परोसना भी आम हो गया है। आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि किस पर भरोसा किया जाए क्योंकि उसके लिए तो मीडिया ही जानकारी का इकलौता साधन है।

पहले पुलवामा हमले की फर्जी तस्वीरें इस कदर लोगों के बीच पहुंचीं कि सीआरपीएफ को खुद सामने आकर फर्जी खबरों से सावधान रहने के लिए कहना पड़ा। हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया ही नहीं, कई बड़े चैनलों पर भी एक आतंकी की फर्जी तस्वीर लोगों को यह कहते हुए दिखाई गई कि पुलवामा का असली गुनहगार यही है! ताजा मामला पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले का है, जिसे दिखाने के लिए मीडिया ने जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी कर दी। इस हमले की तस्वीरें और वीडियो वायरल किए गए, जो फर्जी पाए गए।

चिंताजनक बात यह है कि सोशल मीडिया ही नहीं, टीआरपी की दौड़ में टीवी चैनलों पर बिना जांचे खबर प्रसारित हो रही हैं। अब लोगों को ही खबरों के प्रति ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है।

● *नेहा अधिकारी, चंडीगढ़*

शहीदों का ऋण

वाराणसी में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्ररक्षा के लिए जान न्योछावर करने वाले हर परिवार का हम सभी पर ऋण है। यकीनन, देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए जवानों के हम ऋणी हैं, उनकी बदौलत ही हम चैन की नींद सो पाते हैं। पुलवामा में आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले में देश के 44 जवानों को हमने खोया है। भारत की सहनशीलता का फायदा आतंकियों ने उठाया और बार-बार हमला किया है जिसका सही जवाब दिया गया है। लेकिन विडंबना है कि जिन सैनिकों की बदौलत हमारा देश सुरक्षित रहता है उन्हें बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उन्हें सरकारी पेंशन नहीं मिलती। सरकार को सबसे पहले सैनिकों को पेंशन देने की घोषणा करनी चाहिए और वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए जिनकी उन्हें आवश्यकता है। तभी उन शहीदों का ऋण चुकाया जा सकता है।

सुरक्षा में लापरवाही भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। आखिर आत्मघाती आतंकी गाड़ियों के काफिले में कैसे घुस गया, इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक कैसे और कहां से जुटाया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भाषणों और झूठी घोषणाओं से कभी ऋण नहीं चुकाया गया है। अगर वाकई शहीदों का ऋण चुकाना है तो उनके आश्रितों को नौकरी, मुआवजा, पेंशन की तुरंत घोषणा करें और सैनिकों की रक्षा के लिए सुरक्षा तंत्र विकसित करने की दिशा में ठोस उपाय करें।

● *जफर अहमद, रामपुर डेहरू, मधेपुरा, बिहार*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com